



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269848
CG-DL-E-05022026-269848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

No. 94]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 99(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के अनुसार सभी प्रभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।

2. ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 126 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

126. प्रत्येक मोटर वाहन के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा।

केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 1993 के लागू होने की तारीख से, कृषि ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण वाहन, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, ट्रेलर, सेमी-ट्रेलर और मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर सहित मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता या आयातक, जिसमें ई-रिक्शा के लिए पंजीकृत संघ (संबंधित राज्य परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त) भी शामिल है, अपने द्वारा निर्मित या आयात किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे, या केंद्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुधनी (मध्य प्रदेश), या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, या केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, या इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर, या नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार (कंबाइन हार्वेस्टर के परीक्षण के लिए), या ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई, या नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नैट्रेक्स), इंदौर, या दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश (पावर टिलर के परीक्षण के लिए) और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य एजेंसियां भी अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती हैं।

परंतुक 1

यह भी प्रावधान है कि इस नियम में निर्दिष्ट सभी परीक्षण एजेंसियां, इस नियम के अधीन ऐसे मानकों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर गुणवत्ता मानक, विशेष रूप से एआईएस (ऑटोमोटिव उद्योग मानक) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, और इस नियम के अधीन अधिसूचित की जाने वाली परीक्षण एजेंसियां ऐसे मानकों की अधिसूचना की तारीख या इस नियम के अधीन आवेदन की तारीख, जो भी बाद में हो, से मानक का अनुपालन करेंगी:

परंतुक 2

आगे यह भी प्रावधान है कि इस उप-नियम के अंतर्गत परीक्षण एजेंसियों के प्रत्यायन, पंजीकरण और विनियमन के प्रयोजन के लिए, इस नियम के अंतर्गत अधिसूचित एआईएस में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

परंतुक 3

यह भी प्रावधान है कि इन नियमों के अनुपालन हेतु मोटर वाहनों के प्रकार अनुमोदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 017-2000 या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (यदि कोई हो) के अनुसार होगी और वाहन विनिर्माता द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं संबंधी जानकारी समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-007(संशोधन 5):2014 के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

परंतुक 4

यह भी प्रावधान है कि परिवर्तित, संशोधित या अनुकूलित मोटर वाहनों का परीक्षण और टाइप अनुमोदन इस नियम में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, या मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यशालाओं द्वारा अधिनियम की धारा 52 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार स्व-प्रमाणित किया जाएगा।

परंतुक 5

यह भी प्रावधान है कि वाहन विनिर्माता के संबंध में, जो भारत में दाएं हाथ के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले वाहनों की अप्रयुक्त पूर्णतः निर्मित (सीबीयू) या पूर्णतः अलग-अलग पुर्जों में विभाजित (सीकेडी) इकाइयों का आयात सीधे या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, एम 1 या एल श्रेणी के वाहनों की 2500 इकाइयों तक और अन्य श्रेणियों के वाहनों की 500 इकाइयों तक, जो अंतरराष्ट्रीय मानक, अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानक के अनुरूप हों, ऐसे वाहन की बिक्री और नियम 47 के अधीन पंजीकरण के लिए अनुपालन स्थापित माना जाएगा, जो किसी अधिकृत एजेंसी या मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा जारी संबंधित मानक के अनुपालन प्रमाण पत्र द्वारा सिद्ध होगा।

परंतुक 6

यह भी प्रावधान है कि आयातित एल और एम1 श्रेणी के सभी गैसोलीन-ईंधन वाले वाहनों के लिए, जिनमें सकारात्मक प्रज्वलन इंजन लगा हो, वाहन विनिर्माता को ईईसी, ईसीई या जापानी मानकों के अनुसार संपूर्ण वाहन प्रकार अनुमोदन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 में सूचीबद्ध किसी अधिकृत परीक्षण एजेंसी या ईईसी, ईसीई या जापानी मानकों के अनुसार वाहन प्रकार अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने वाली किसी अधिकृत परीक्षण एजेंसी द्वारा ई20 संदर्भ ईंधन (समय-समय पर यथा संशोधित आईएस:17943 के अनुसार) पर किए गए टाइप-1 निकास उत्सर्जन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मानक, अर्थात् ईईसी, ईसीई या जापानी मानकों में लागू उत्सर्जन परीक्षण चक्र पर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वाहन विनिर्माताओं को उक्त रिपोर्ट के साथ ई20 ईंधन के लिए सामग्री अनुकूलता की घोषणा भी अधिकृत परीक्षण एजेंसी को प्रस्तुत करनी होगी।

परंतुक 7

यह भी प्रावधान है कि कृषि ट्रैक्टरों के प्रकार अनुमोदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एआईएस-017 (भाग 2) (संशोधन 2): 2016 मानक के अनुसार होगी, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हों।

परंतुक 8

यह भी प्रावधान है कि यदि भारत में पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में निजी उपयोग, प्रदर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्य से आयात किए गए अंतरराष्ट्रीय मानक, अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानक के अनुरूप अप्रयुक्त दाएं हाथ के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले वाहन हों, तो नियम 47 के अधीन पंजीकरण के लिए ऐसे वाहनों का अनुपालन किसी अधिकृत एजेंसी या मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा जारी संबंधित मानक के अनुपालन प्रमाण पत्र द्वारा स्थापित माना जाएगा।

परंतुक 9

यह भी प्रावधान है कि निर्माण उपकरण वाहनों (सीईवी) में दोनों तरफ स्टीयरिंग नियंत्रण हो सकता है:

परंतुक 10

यह भी प्रावधान है कि ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस), टाइप अनुमोदन प्रक्रिया 115/116, भारतीय मानक (आईएस) और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) मानकों में शुद्धिपत्र, संशोधन या पुनरीक्षण से निपटने की प्रशासनिक प्रक्रिया, जो केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन अधिसूचित की जाती हैं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-000:2013 के अनुसार होगी।

परंतुक 11

यह भी प्रावधान है कि ट्रक बॉडी के प्रोटोटाइप को परीक्षण और टाइप अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को प्रस्तुत किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11028/09/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2026

G.S.R. 99(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (g) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

The Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. **Short title and title and Commencement:** (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 126, the following shall be substituted, namely:

“126. **Prototype of every motor vehicle to be subject to test.**—

On and from the date of commencement of Central Motor Vehicle (Amendment) Rules, 1993, every manufacturer or importer of motor vehicles including Agricultural Tractor, Construction Equipment Vehicle, Combine Harvester, Power Tillers, Trailers, semi-trailers and Modular Hydraulic Trailers, including registered association (identified by concerned State Transport department) for E-rickshaw, shall submit the prototype of the Vehicle to be manufactured or imported by him for test by the Vehicle Research and Development Establishment of the Ministry of Defence of the Government of India or Automotive Research Association of India, Pune, or the Central Farm Machinery Testing and Training Institute, Budni (MP), or the Indian Institute of Petroleum, Dehradun, or the Central Institute of Road Transport, Pune, or the International Centre for Automotive Technology, Manesar, or the Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (for testing of Combine Harvester), or the Global Automotive Research Centre, Chennai, or the National Automotive Test Tracks (NATRAX), Indore, or the Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur, Andhra Pradesh (for testing of Power Tiller) and such other agencies as may be specified by the Central Government for granting a certificate by that agency as to the compliance of provisions of the Act and these rules.

Proviso 1

Provided that all the testing agencies specified in this rule, shall establish compliance with the quality standard, specifically AIS (Automotive Industry Standard), within one year from the date of publication of such standards under this rule, and the testing agencies to be notified under this rule shall be in compliance with the standard from the date of notification of such standards or date of application under this rule, whichever is later:

Proviso 2

Provided further that for the purpose of accreditation, registration and regulation of testing agencies under this sub-rule, the quality control and procedure prescribed in AIS notified under this rule shall be followed:

Proviso 3

Provided also that the procedure for type approval and certification of motor vehicles for compliance to these rules shall be in accordance with the AIS: 017-2000, as amended from time to time, or procedure laid down by the Central Government, if any and information on technical specifications shall be submitted by the vehicle manufacturer in accordance with AIS-007(Rev.5):2014, as amended from time to time:

Proviso 4

Provided also that altered, retrofitted or adapted motor vehicles shall be tested and type approved by the testing agencies specified in this rule, or self- certified by original equipment manufacturers, or self-certified by the work-shops authorized by the State Government, in accordance with section 52 of the Act and rules made thereunder:

Proviso 5

Provided also that in respect of vehicle manufacturer, importing into India unused completely built units (CBU) or completely knocked down units (CKD) of right hand steering control vehicles, directly or through their authorised representative, up to 2500 units of M 1 or L category of vehicles, as the case may be and up to 500 units of other categories of vehicles annually, compliant with international standard, namely EEC or ECE or Japanese, the compliance of such vehicle shall be deemed to be established for sale and registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Proviso 6

Provided also that, for all imported L and M1 category gasoline-fuelled vehicles equipped with positive ignition engine, the vehicle manufacturer in addition to whole vehicle type approval certificate as per EEC, ECE, or Japanese standards shall provide a Type-I exhaust emission compliance report performed on E20 reference fuel (as per IS :17943 as amended from time to time), issued by an authorized test agency listed in the Rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, or by an authorized test agency issuing vehicle type approval certificate as per EEC, ECE, or Japanese standards, performed on emission test cycle applicable in international standard, namely EEC, ECE or Japanese and such. Further the vehicle manufacturers along with the said report shall submit a declaration for material compatibility for E 20 fuel to the authorized test agency:

Proviso 7

Provided also that the procedure for type approval and certification of agricultural tractors shall be in accordance with AIS-017(Part 2) (Rev.2): 2016 standard as amended from time to time:

Proviso 8

Provided also that in respect of unused right-hand steering control vehicles compliant with the international standard namely, EEC or ECE or Japanese, imported into India as completely built units (CBU), for the purpose of personal use, demonstration, testing, research or scientific work, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Proviso 9

Provided also that the construction equipment vehicles (CEV) may have steering control on either of the side:

Proviso 10

Provided also that the administrative procedure to deal with corrigendum, amendments or revisions to Automotive Industry Standards (AIS), Type Approval Procedures 115/116, Indian Standards (IS) and International Organisation for Standardisation (ISO) standards, which are notified under the Central Motor Vehicles Rules, 1989, shall be in accordance with AIS-000:2013 as amended from time to time:

Proviso 11

Provided also that prototype of truck bodies may be submitted for testing and type approval to engineering colleges specified by the State Government or the State Road Transport Undertakings duly approved by the State Government.”

[F. No RT-11028/09/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R.(E) dated the ..